

SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)



विकसित भारत 2047: आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास

केशव कुमार सोनी, पीएच.डी., राजनीति विज्ञान
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Author

केशव कुमार सोनी, पीएच.डी.
E-mail : keshavsoni880@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 12/12/2025
Revised on : 13/02/2026
Accepted on : 22/02/2026
Overall Similarity : 00% on 14/02/2026



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

0%

Overall Similarity

Date: Feb 14, 2026 (06:09 PM)
Matches: 0 / 3502 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found,
your document looks healthy.

Verify Report:
Scan this QR Code



शोध सार

भारत ने अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक "विकसित राष्ट्र" बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य केवल तीव्र आर्थिक वृद्धि तक सीमित न होकर सामाजिक समावेशन, मानव विकास, संस्थागत सुदृढ़ता और सतत विकास जैसे व्यापक आयामों को सम्मिलित करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य "विकसित भारत 2047" की अवधारणा का आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास के दृष्टिकोण से समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में मानव विकास दृष्टिकोण, समावेशी विकास सिद्धांत तथा हालिया राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आँकड़ों को सैद्धांतिक आधार बनाया गया है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, डिजिटल अवसंरचना, सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु क्षेत्रीय विषमता, आय-असमानता, रोजगार सृजन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र यह रेखांकित करता है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय, मानव क्षमताओं के विस्तार और सतत नीतिगत सुधारों के साथ संतुलित किया जाए।

मुख्य शब्द

विकसित भारत 2047, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव विकास, समावेशी विकास, सतत विकास.

भूमिका

स्वतंत्रता के बाद से भारत की विकास यात्रा निरंतर प्रगतिशील रही है, तथा वर्ष 2047 को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने की परिकल्पना ने इस यात्रा को एक नए उच्चतम स्तर तक पहुँचाया है। 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन

से मुक्ति पाने के बाद भारत ने योजनाबद्ध विकास, सामाजिक समावेशन तथा आर्थिक सशक्तीकरण को अपने राष्ट्रीय एजेंडा के केंद्र में रखा। प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाएँ कृषि, बुनियादी अवसंरचना तथा सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती थीं, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नींव रखना था। समय के साथ, आर्थिक उदारीकरण (LPG नीति) 1991 में लागू होने के पश्चात् भारत ने वैश्वीकरण के साथ एक अधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना शुरू किया।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की परिकल्पना अब केवल परिपक्व आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेशन, तकनीकी प्रगति, मानव क्षमताओं का विस्तार तथा सतत विकास जैसे बहुआयामी लक्ष्य शामिल करती है। “विकसित भारत 2047” का लक्ष्य देश को उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसरों को समग्र रूप से उन्नत किया जाए। नीति आयोग सहित विभिन्न नीतिगत अभिकरणों के अनुसार, भारत की वास्तविक ळक्च को 2047 तक लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान के लगभग पाँच गुना से अधिक है, यदि यह लक्ष्य प्राप्त होता है तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को और सुदृढ़ करेगा।¹

आर्थिक आयामों के अलावा मानव विकास के संकेतक भी समग्र प्रगति को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत का HDI (Human Development Index) मान 2023 में 0.644 तक बढ़ गया है, जिससे भारत 134वीं स्थिति में आया है (193 देशों में), जो मध्यम मानव विकास श्रेणी में सुधार को दर्शाता है।² इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि भारत न केवल आय वृद्धि में बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा जैसे मानवीय संकेतकों पर भी प्रगति कर रहा है।

आर्थिक वृद्धि दर भारत के विकास लक्ष्य का एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 2021 से 2024 तक भारत की उच्च वृद्धि दर औसतन 7 प्रतिशत से अधिक रही है, जिसमें कुछ वर्षों में यह 8.2 प्रतिशत तक रिकॉर्ड की गई है, जो वैश्विक मंदी की चुनौती के बावजूद एक मजबूत प्रदर्शन का संकेत है।³ विश्व बैंक की रिपोर्ट यह सुझाव देती है कि यदि भारत 2047 तक उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो उसे लगभग 7.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने की आवश्यकता होगी।⁴ यह आंकड़ा देश की विकास गति और नीति-परिवर्तन की आवश्यकता को दोनों ही दर्शाता है।

जैसा कि अमर्त्य सेन ने उल्लेख किया है:

“Development is the process of expanding the real freedoms that people enjoy.”⁵

इस सैद्धांतिक आधार पर विकसित भारत की परिकल्पना न केवल आर्थिक वृद्धि बल्कि मनुष्यों के सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशन और उनके अधिकारों की विस्तृति पर केन्द्रित है।

विकास की इस परिकल्पना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और स्त्री-शक्ति का सशक्तीकरण महत्वपूर्ण घटक हैं। शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जिसका लक्ष्य बहुविषयक शिक्षा, कौशल-आधारित प्रशिक्षण और अनुसंधान को बल देना है। स्वास्थ्य के मामले में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने का प्रयास किया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार देखने को मिला है।

भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की विविधता उसे विकासशील चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देती है, परंतु इस विविधता में असमानता भी विद्यमान है। क्षेत्रीय विषमताएँ, लैंगिक भेद, ग्रामीण-शहरी विभाजन और रोजगार असुरक्षा जैसी चुनौतियाँ अभी भी विकास की गति को प्रभावित करती हैं। इस संदर्भ में, विकसित भारत का लक्ष्य समावेशी नीति-निर्माण के माध्यम से इन विषमताओं को कम करना भी है।

विकसित भारत 2047 की अवधारणा

भारत का "विकसित भारत 2047" कार्यक्रम राष्ट्र की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को एक पूर्ण विकसित और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परिकल्पना है। यह अवधारणा केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेशन, तकनीकी प्रगति, मानव क्षमता का विस्तार, पर्यावरणीय सततता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी समाहित करती है। वर्ष 2047 का चुनाव ऐतिहासिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है—यह स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के रूप में राष्ट्र के लिए एक प्रतीकात्मक लक्ष्य भी है और दीर्घकालिक नीति-प्रणाली के लिए एक स्थिर समय सीमा भी।⁶

"विकसित भारत 2047" की अवधारणा में अर्थव्यवस्था, सामाजिक निर्माण, तकनीकी और संस्थागत सुदृढ़ता को समन्वित रूप से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक संदर्भ में विकसित राष्ट्रों की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, नीति-निर्माताओं का मानना है कि विकसित देश वह होता है जहाँ उच्च प्रति व्यक्ति आय, व्यापक मानव विकास संकेतक (HDI), उच्च गुणवत्ता का जीवन स्तर, प्रगतिशील तकनीकी आधार और पर्यावरण-अनुकूल नीति लागू होती हैं।⁷

आर्थिक सिद्धांत और लक्ष्य

आर्थिक दृष्टि से "विकसित भारत 2047" का लक्ष्य है भारत को एक हाई-इनकम अर्थव्यवस्था बनाना तथा उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। विभिन्न अध्ययनों और नीतिगत दस्तावेजों के अनुसार, भारत की GDP को 2047 तक लगभग 23-35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (USD) के बीच पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद से कई गुना अधिक है। यह आंकड़ा देश को एक उच्च-आय वाले राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित करने में सहायक माना जाता है।⁸

इन अनुमानों के अनुसार भारत को अगले दो दशक में औसतन 8-10 प्रतिशत वार्षिक GDP वृद्धि दर हासिल करनी होगी ताकि यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उच्च विकास दर का सीधा प्रभाव प्रति-व्यक्ति आय (Per Capita Income) में भी देखा जाएगा। अनुमान है कि 2047 तक प्रति-व्यक्ति आय 15,000 से 18,000 USD के स्तर तक पहुंच सकती है, जो आज की कम-आय स्थिति से अत्यधिक प्रगति का संकेत है।⁹

सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025 जैसे दस्तावेजों में वर्णित है कि यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे लगातार 7-8 प्रतिशत से अधिक के वास्तविक GDP विकास दर को दो दशकों से अधिक समय तक बनाए रखना होगा। इस प्रकार की निरंतर वृद्धि न केवल आर्थिक शक्ति को बढ़ाती है बल्कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, और सामाजिक निवेश के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराती है।¹⁰

मानव विकास और सामाजिक समावेशन

विकसित भारत 2047 की अवधारणा का एक अन्य प्रमुख तत्व मानव विकास है। केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है; सामाजिक संकेतकों—जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, और मानव विकास सूचकांक (HDI)—का भी निरंतर उन्नति होना आवश्यक है। अनुमान है कि 2047 तक भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी से उभरकर उच्च मानव विकास श्रेणी (High HDI) में प्रवेश कर सकता है। यह परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा सुधार, साक्षरता दर में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में सुधार और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है।¹¹

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि भारत को अपनी मानव विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच, पोषण और आय सुरक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए ताकि सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचे। इस दृष्टिकोण में समावेशी विकास (Inclusive Development) की भावना निहित है, जिसमें सामाजिक असमानताओं को कम करना विकास का एक अभिन्न पहलू माना जाता है।¹²

तकनीकी प्रगति और नवाचार

तकनीकी उन्नति "विकसित भारत 2047" की अवधारणा का एक और सूक्ष्म आयाम है। दुनिया भर में तकनीक-आधारित प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और भारत ने डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश की योजना बनाई है ताकि वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत की हिस्सेदारी को मजबूत किया जा सके। जैसा कि रिपोर्टों में सामने आया है, तकनीकी प्रगति और सुधार से कुल फैक्टर उत्पादकता (TFP) और रोजगार निर्माण भी बढ़ता है।¹³

विशेष रूप से, भारत को अपने R&D (Research and Development) व्यय को बढ़ाकर ळक्च का लगभग 3 प्रतिशत तक ले जाने की आवश्यकता बताई गई है—जिससे नई तकनीकों के विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में R&D खर्च लगभग GDP का 0.65 प्रतिशत ही है, जो अन्य तकनीकी उन्नत देशों की तुलना में कम है।¹⁴

सततता और संस्थागत सुधार

"विकसित भारत 2047" की अवधारणा स्थायी विकास (Sustainable Development) को भी प्राथमिकता देती है। यह न केवल पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा और कृषि नीतियों को शामिल करती है, बल्कि अच्छे शासन (Good Governance), पारदर्शिता, और नागरिक केंद्रिक नीतियों को भी मजबूती देती है ताकि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का संतुलित समाधान सुनिश्चित हो सके।

उदाहरण

ज्योति बसु ने एक संबोधन में कहा था:

"Vision without action is merely a dream; action without vision just passes the time. Vision with action can change the world."

यह उदाहरण विकसित भारत 2047 की अवधारणा के लिए प्रेरक है—क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि विकास का लक्ष्य केवल कल्पना नहीं, बल्कि सुदृढ़ रणनीति और क्रियान्वयन के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

सैद्धांतिक ढाँचा

"विकसित भारत 2047" की अवधारणा को समझने के लिए एक सुदृढ़ सैद्धांतिक ढाँचे की आवश्यकता है, क्योंकि यह लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, मानव विकास और सतत प्रगति जैसे व्यापक आयामों से जुड़ा हुआ है। सैद्धांतिक ढाँचा मुख्यतः मानव विकास दृष्टिकोण, समावेशी विकास सिद्धांत, और सतत विकास सिद्धांत पर आधारित है, जो मिलकर विकसित भारत की परिकल्पना को वैचारिक आधार प्रदान करते हैं।

मानव विकास दृष्टिकोण

मानव विकास दृष्टिकोण का प्रतिपादन अमर्त्य सेन और महबूब-उल-हक द्वारा किया गया, जिसमें विकास को आय या उत्पादन की वृद्धि के बजाय मानव क्षमताओं (capabilities) के विस्तार के रूप में देखा गया है। अमर्त्य सेन के अनुसार:

"Development is the process of expanding the real freedoms that people enjoy."¹⁵

इस दृष्टिकोण के अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सम्मानजनक जीवन—स्तर विकास के केंद्रीय घटक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक (HDI) इसी सैद्धांतिक आधार पर निर्मित है। UNDP की Human Development Report 2023 के अनुसार भारत का HDI मान लगभग 0.644 है, जो यह दर्शाता है कि भारत ने मानव विकास के क्षेत्र में प्रगति की है, किंतु अभी भी उच्च मानव विकास श्रेणी तक पहुँचने के लिए व्यापक सुधार आवश्यक हैं। यह डेटा इस बात को रेखांकित करता है कि विकसित भारत 2047

का लक्ष्य मानव विकास में गुणात्मक छलांग से जुड़ा हुआ है।

समावेशी विकास सिद्धांत

समावेशी विकास सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचना चाहिए। यह सिद्धांत विशेष रूप से विकासशील देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहाँ आर्थिक प्रगति के बावजूद असमानता बनी रहती है। भारत में क्षेत्रीय विषमता, आय-असमानता और सामाजिक बहिष्करण जैसी समस्याएँ इस सिद्धांत की प्रासंगिकता को और बढ़ा देती हैं। विश्व बैंक के अनुसार, दीर्घकालिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह गरीबी में कमी, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के साथ जुड़ा हो।¹⁶

“विकसित भारत 2047” की अवधारणा में समावेशी विकास का आशय यह है कि महिलाएँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अल्पसंख्यक और ग्रामीण आबादी विकास प्रक्रिया में समान भागीदारी करें। यह दृष्टिकोण आर्थिक न्याय और सामाजिक स्थिरता को सुदृढ़ करता है।

सतत् विकास सिद्धांत

सतत् विकास सिद्धांत “विकसित भारत 2047” के सैद्धांतिक ढाँचे का तीसरा प्रमुख आधार है। ब्रुटलैंड आयोग (1987) के अनुसार:

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”¹⁷

भारत जैसे देश के लिए, जहाँ जनसंख्या दबाव और पर्यावरणीय चुनौतियाँ गंभीर हैं, यह सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है और वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। यह संकेत करता है कि विकसित भारत 2047 की दिशा में पर्यावरण-अनुकूल विकास एक आवश्यक शर्त है।

आर्थिक विकास

आर्थिक विकास “विकसित भारत 2047” की परिकल्पना का केंद्रीय स्तंभ है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति और मानव विकास का आधार उसकी आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से योजनाबद्ध विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और बाद में उदारीकरण आधारित नीतियों के माध्यम से आर्थिक संरचना को सुदृढ़ किया है। विशेष रूप से 1991 के बाद लागू आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा और विकास की गति को तीव्र किया।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 2022-24 के दौरान औसतन 7 प्रतिशत से अधिक रही है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है।¹⁸ वर्ष 2023-24 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया, जिससे भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,500 अमेरिकी डॉलर के आसपास आँकी गई, जो निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।¹⁹

आर्थिक विकास का महत्व केवल राष्ट्रीय आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। भारत सरकार की Make in India, Digital India, Startup India और PM Gati Shakti जैसी पहलें औद्योगीकरण, अवसंरचना विकास और नवाचार को प्रोत्साहित कर रही हैं। इन नीतियों के परिणामस्वरूप विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था का तीव्र विस्तार हुआ है। हालाँकि, आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया कुछ संरचनात्मक चुनौतियों से भी घिरी हुई है। बेरोजगारी, आय-असमानता, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व और क्षेत्रीय विषमताएँ अभी भी भारत की

आर्थिक प्रगति को सीमित करती हैं। इसी संदर्भ में अमर्त्य सेन का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है:

“Economic growth is not an end in itself; it is a means to expanding human lives.”²⁰

“विकसित भारत 2047” की दृष्टि से आर्थिक विकास का आशय ऐसी समावेशी और टिकाऊ वृद्धि से है, जो समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। नीति आयोग और विश्व बैंक के अनुसार, यदि भारत को 2047 तक उच्च-आय वाला देश बनना है, तो उसे दीर्घकाल तक 7–8 प्रतिशत की सतत विकास दर बनाए रखनी होगी। यह तभी संभव है जब आर्थिक नीतियों को मानव विकास, कौशल निर्माण और सामाजिक न्याय के साथ संतुलित किया जाए।²¹

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास “विकसित भारत 2047” की परिकल्पना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन-स्तर की गुणवत्ता से किया जाता है। भारत जैसे बहुविविध समाज में सामाजिक विकास का अर्थ है—विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करना और ऐतिहासिक असमानताओं को कम करना।

सामाजिक विकास का प्रमुख आधार शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हालिया सरकारी आँकड़ों के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 2011 के 74 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में लगभग 80.09 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है। 22 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुविषयक शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और समान अवसरों पर विशेष बल दिया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का यह कथन सामाजिक विकास के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है:

“Education is the milk of a lioness; whoever drinks it roars.”²³

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM&JAY) के अंतर्गत करोड़ों परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। NFHS-5 और हालिया स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी दर्ज की गई है, जो सामाजिक विकास की दिशा में सकारात्मक संकेत है साथ ही, जीवन प्रत्याशा बढ़कर लगभग 70 वर्ष के आसपास पहुँच चुकी है।²⁴

सामाजिक विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय और समावेशन है। भारतीय संविधान ने समानता और सामाजिक न्याय को मूल अधिकारों के रूप में स्थापित किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, जिन समाजों में असमानता कम होती है, वहाँ विकास अधिक टिकाऊ और स्थिर होता है।²⁵

हालाँकि, सामाजिक विकास की प्रक्रिया चुनौतियों से मुक्त नहीं है। ग्रामीण-शहरी अंतर, लैंगिक असमानता, डिजिटल डिवाइड और क्षेत्रीय विषमताएँ अभी भी बनी हुई हैं। इसी संदर्भ में अमर्त्य सेन का यह विचार महत्वपूर्ण है:

“Social arrangements should aim at expanding people's capabilities.”²⁶

“विकसित भारत 2047” की दृष्टि से सामाजिक विकास का अर्थ है ऐसी नीतियाँ अपनाना जो आर्थिक वृद्धि के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएँ। जब शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का समान वितरण सुनिश्चित होगा, तभी भारत वास्तव में एक विकसित और समावेशी राष्ट्र बन सकेगा।

निष्कर्ष

“विकसित भारत 2047” की परिकल्पना भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक एक समृद्ध, समावेशी और मानवीय राष्ट्र के निर्माण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह अध्ययन दर्शाता है कि विकसित राष्ट्र बनने

की प्रक्रिया केवल तीव्र आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, मानव विकास, संस्थागत सुदृढ़ता और सततता जैसे आयामों का संतुलित समावेशन अनिवार्य है। भारत ने हाल के दशकों में आर्थिक वृद्धि, डिजिटल अवसंरचना, सामाजिक कल्याण योजनाओं और वैश्विक आर्थिक सहभागिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश में विकसित राष्ट्र बनने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन में निरंतर निवेश मानव विकास को गति प्रदान करता है और सामाजिक असमानताओं को कम करने में सहायक होता है। मानव विकास दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विकास का अंतिम उद्देश्य मानव क्षमताओं का विस्तार और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। इस संदर्भ में भारत के सामने आय-असमानता, क्षेत्रीय विषमता, बेरोज़गारी और पर्यावरणीय चुनौतियाँ अभी भी महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं।

निष्कर्षतः, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब नीति-निर्माण में दीर्घकालिक दृष्टि, सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाए। आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और मानव विकास के बीच संतुलन स्थापित कर भारत न केवल एक उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है, बल्कि एक ऐसा समाज भी निर्मित कर सकता है जहाँ समान अवसर, गरिमा और सतत प्रगति सुनिश्चित हो। इस प्रकार, विकसित भारत 2047 एक व्यवहारिक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है, बशर्ते विकास को समग्र और समावेशी दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए।

संदर्भ सूची

1. 2047 Growth Strategy and Targets. Viksit Bharat 2047 Detailed Goals, , <https://viksitindia.com/> , Accessed on 10/11/2025.
2. Brundtland G. H. (1987) *Our Common Future*. United Nations, New York.
3. Developed India 2047 Goals. *Sanskriti IAS*, <https://www.sanskritiias.com/hindi/current-affairs/developed-india-2047-indias-ambition-to-become-an-economic-superpower> , Accessed on 15/11/2025.
4. Economic Survey 2025 and Growth Rate Requirements. *OneIndia Hindi Economic Survey Summary*, <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/jan/doc2026130774501.pdf#:~:text=India's%20growth%20remains%20robust%2C%20with%20real%20GDP,manufacturing%20gaining%20momentum%2C%20and%20services%20leading%20expansion>. Accessed on 12/11/2025.
5. Government of India (2020) *National Education Policy 2020*. Ministry of Education, New Delhi.
6. Government of India (2023) *Economic Survey of India*. Ministry of Finance, New Delhi.
7. Government of India (2023) *National Family Health Survey (NFHS-5) Highlights*. Government of India, New Delhi.
8. भारत का विज़न 2047: विकसित भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था. Next IAS Current Affairs Team, 2024, <https://www.nextias.com/ca/editorial-analysis-hindi/22-08-2024/भारत-2047-तक-30-ट्रिलियन-डॉलर-की>, Accessed on 16/11/2025.
9. <https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/india-can-be-a-55-trillion-economy-by-2047-with-8-real-growth-says-imf-executive-director/article68502090.ece> , Accessed on 15/11/2025.

10. India's Growth Story and 2047 Projections. *NDTV Economic Analysis*, , <https://www.drishtias.com/daily-updates/daily-news-editorials/vision-india-2047-transforming-the-nation-future>, Accessed on 13/11/2025.
11. Ashraf, Amrah (2025) United Nations Development Programme (UNDP), One United Nations Plaza, New York
12. Projected GDP and High Income Goals. *NDTV Business Report (GDP 23–35 Trillion)*, <https://www.thehindubusinessline.com/economy/sectoral-growth-technology-and-global-competitiveness-to-power-indias-2335-trillion-economic-vision-by-2047-nasscom-bain-company-report/article69242378.ece> , Accessed on 16/11/2025.
13. Sen, Amartya (1999) *Development as Freedom*. Oxford University Press, New Delhi.
14. <https://visionias.in/current-affairs/upsc-daily-news-summary/article/2025-06-24/business-standard/economy/viksit-bharat-by-2047-goal-are-we-on-track-for-tech-advancement> , Accessed on 17/11/2025.
15. UNDP. (2023) *Human Development Report*. United Nations Development Programme, New York.
16. Viksit Bharat 2047: Goals and Pillars. *Viksit India Vision Document*, <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3kv05b90e8875c131d0760d04c0d4d8f3/uploads/2025/08/2025080227.pdf> , Accessed on 19/11/2025.
17. Viksit India 2047 Vision Report. *Viksit Bharat 2047 Website*, <https://viksitindia.com/> Accessed on 22/11/2025.
18. World Bank (2024) *World Development Indicators*. World Bank Publications, Washington.
19. World Bank (2025) *India Country Economic Memorandum: Becoming a High-Income Economy in a Generation*. World Bank Publications, Washington.
